संख्या-1/2015/1805/43-1-2014-7(4)/(2013)

प्रेषक,

भवेश रंजन
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
उ0प्र0राज्य सूचना आयोग,
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ - दिनांक 02 जनवरी, 2015

विषय-: अनुदान संख्या-46 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखाशीर्षक--2070 में अनुपूरक अनुदान से आयोजनेत्तर मद में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त करते हुए सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-433/रा0सू0आ0/2014, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014- 15आय-व्ययक में अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर -03-उ0प्र0 सूचना आयोग का गठन के विभिन्न मानक मदों में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 25,00,000/- (रूपये पच्चीस लाख मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल स्वीक़त चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में धनराशि का उपयोग नई सेवाओं और मदों पर न किया जाय।

2- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन एलॉटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हों, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये।

- - - 2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जनू, 1994 एवं दिनांक 24-10-2013 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सी0ए0–1191/दस–2009–मित0–1/2007, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 का विशेष रूप से पालन किया जाये तथा राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों(स्टैन्र्डस फाइनेंशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग संलग्नक में दर्शायी गयी मदों में ही किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि का डाइवरजन बिना शासन की पूर्व अनुमति के कदापि न किया जाय तथा किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुदान संख्या-46 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 सूचना आयोग का गठन के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं।

संलग्क- यथोक्त।

भवदीय,

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

संख्या- /1805 (1)/43-1-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- लेखाकार, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- -1805/43-1-2014 दिनांक दिसम्बर, 2014 का संलग्नक।

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित/अवमुक्त की जानी वाली धनराशि
1	2
02-मजदूरी	700
04-यात्रा व्यय	100
08-कार्यालय व्यय	900
09-विद्युत देय	200
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	200
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	200
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	100
योग-	2500

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।